

प्राक्कथन

मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) का एक सुदीर्घ और विविधतापूर्ण इतिहास है, जो स्वयं भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था, जिसमें 1935-36 और 1936-37 के वर्ष लिए गए थे।

2. एक संस्था के रूप में आरबीआई के लिए वे प्रारंभिक वर्ष थे, जिनमें इतिहास लिखा नहीं बल्कि बनाया जा रहा था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अस्तित्व में आया। पहली बार बैंक दर की आधिकारिक तौर पर घोषणा 4 जुलाई को की गई थी जो 3.5 प्रतिशत थी। इसके बाद अगले दिन आधिकारिक तौर पर तथाकथित अनुसूचित बैंकों [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(ए) के तहत निर्धारित मानदंड को पूरा करने पर अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल] से संपर्क किया गया जो आरबीआई से बैंक दर पर ऋण/कर्ज और समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) की सदस्यता के पात्र हुए। उस वर्ष, आरबीआई ने 9 महीने की अवधि को कवर करते हुए अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की और ₹ 56.055 लाख रुपये के शुद्ध लाभ के साथ 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का लाभांश घोषित किया। 1 अप्रैल, 1935 को 92,047 शेयरधारक थे लेकिन 31 दिसंबर, 1936 तक यह संख्या गिरकर 66,273 हो गई थी।

3. जब अप्रैल 1935 में निर्गम विभाग ने भारत सरकार से मुद्रा का प्रबंधन अपने हाथ में लिया तो मुद्रा नियंत्रक (कंट्रोलर ऑफ़ करेंसी) द्वारा तैयार की जा रही वार्षिक मुद्रा रिपोर्ट बंद कर दी गई। फलस्वरूप इसे फिर से शुरू करने के लिए उठ रही आवाजों को देखते हुए, 'सांख्यिकीय निरंतरता'¹ के हित में आरबीआई इसके लिए तैयार हुआ। यह देखते हुए कि एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही थी और एक मासिक और वार्षिक सांख्यिकीय सारांश भी था, आरबीआई ने निर्णय लिया कि एक वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की जाए जो अलग हो: सामान्यतः यह पिछली मुद्रा रिपोर्टों के ढाँचे पर आधारित हो, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्माण के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन सहित उस समय का विवरण देने वाले घटनाक्रम और आंकड़ों पर एक टिप्पणी के साथ। यह निर्णय लिया गया कि यह रिपोर्ट 'प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके वार्षिक रूप में प्रकाशित की जाए' (आरबीआई, 2005)²।

4 उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर समष्टि आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी द्वारा पहली रिपोर्ट (1937) ने एक रुख तय कर दिया। पण्य उत्पादक देश महामंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए। भारत में, कच्चे माल की बढ़ती मांग के चलते, सामान्य कीमतें बढ़ीं जो उस समय कलकत्ता थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती थीं। कपास और जूट विनिर्माणों, लोहा और इस्पात, और चीनी के उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ। गैर-अटकलिया (नॉन स्पेक्यूलेटिव) शेयरों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, और अटकलिया (स्पेक्यूलेटिव) शेयर हल्की गति से उनके पीछे रहे। वाणिज्य वस्तु व्यापार के संतुलन ने उल्लेखनीय सुधार दिखाते हुए 'विदेशी मुद्रा' ('एक्सचेंज') को मजबूत रखा, जिससे आरबीआई ने सरकार को £16,858,000 की राशि वाले 5.5 प्रतिशत इंडिया बॉण्ड्स 1936-38 को चुकाने की स्थिति में ला दिया। आसान मुद्रा बाजार स्थितियां बनी रहीं और बैंक दर के 0.5 प्रतिशत घटकर 3 प्रतिशत होने में परिलक्षित हुई। बजट अधिशेष दर्ज हुआ और रिकॉर्ड निम्न ब्याज दरों पर रिकॉर्ड उधारियां हुईं। बर्मा भारत से अलग हुआ (1937) और सिंध और उड़ीसा के नए प्रांत बनाए गए (1936)। चुपचाप और बिना किसी तड़क-भड़क के, आरबीआई में एक तीसरी आवाज का जन्म हुआ - संस्था के पेशेवर अनुसंधान की आवाज।

1,2 मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, 1937, भूमिका (पैरा 1)।

5. स्वतंत्रता के बाद, आरसीएफ की विषयवस्तु को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया था - अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम; और भारतीय मुद्रा और वित्त। 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में इसकी विषयवस्तु में परिवर्तन देखा गया। उन दिनों राष्ट्रीय आख्यान पर हावी बदलते राजनीतिक-सामाजिक समीकरण के कारण, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से ध्यान घटा और आरसीएफ का ध्यान उत्तरोत्तर अंदर की ओर मुड़ा। इसकी विषयवस्तु तीन भागों में बँटी - भारत का समष्टि आर्थिक घटनाक्रम; उत्पादन और कीमत के रुझान; और सांख्यिकीय विवरण। 1974-75 से 1997-98 तक, आरसीएफ के दो खंड प्रकाशित हुए - खंड I में एक आर्थिक समीक्षा कवर की जाती थी और खंड II में सांख्यिकीय विवरण होते थे।

6. वर्ष 1998-99 आरसीएफ के इतिहास में एक नए मोड़ और इसके आख्यान में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में सामने आया। अपने सामान्य वर्णनात्मक क्रमागत अभिलेखीकरण से महत्वपूर्ण रूप से हटते हुए, आरसीएफ ने एक विषय-आधारित दृष्टिकोण अपनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को हाथ में लिया। उस समय की घटनाओं ने इस उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए एकदम सही संदर्भ प्रदान किया। भारतीय अर्थव्यवस्था एक चक्रीय मंदी से उभर रही थी और परिवर्तन के साथ-साथ आपूर्ति के आघात भी लगे जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया। बाह्य परिवेश एशियाई वित्तीय संकट के परिणामी आघातों से ग्रस्त था तथा यह संक्रमण रूस और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में फैल गया। अपने परमाणु परीक्षण के चलते भारत को कई देशों के प्रतिबंधों और रेटिंग में गिरावटों का सामना करना पड़ा, जिसे देखते हुए विदेशों में रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड जारी किए गए।

7. लेकिन इतिहास करवट ले रहा था। 1950 के दशक की शुरुआत से केंद्रीकृत योजना के परिणाम अक्षमताओं, विकृतियों और नीतियों व परिस्थितियों के दुरुपयोग वाली गतिविधियों के रूप में सामने आए। 1990 के दशक की शुरुआत में, भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। यद्यपि इसकी शुरुआत तो खाड़ी युद्ध, तत्कालीन यूएसएसआर के विघटन, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और आवक धन-प्रेषणों के सूखने जैसे बाहरी कारणों के चलते हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था के तत्संबंधी आधारभूत पक्षों की अव्यवहार्यता एकदम साफ़ थी। 1990 के दशक के बाकी हिस्सों में सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला और बाजारोन्मुखता और खुलेपन की दिशा में विकास रणनीति में परिवर्तन द्वारा संरचनात्मक सामंजस्य किया गया। जैसा कि आरसीएफ ने उल्लेख किया है, अर्थव्यवस्था ने नई सहस्राब्दी की दहलीज पर अत्यंत सुदृढ़ता और गतिशीलता दर्शाई और इसने आरसीएफ के विषय हेतु आधार दिया। परिणाम यह हुआ कि, इस नए मोड़ के बाद आने वाले आरसीएफ के अंकों ने परिवर्तन के मूलतत्त्व को आत्मसात किया। अगले दशक में, अन्य विकासपरक विषय भी लिए गए: वित्तीय क्षेत्र और बाजार एकीकरण; वृद्धि को पुनर्जीवन; सुधार प्रक्रिया और उसके परिणामों का आकलन; एक खुली अर्थव्यवस्था वाली संरचना में बाह्य क्षेत्र का प्रबंधन; मौद्रिक नीति का विकास; भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास; वित्तीय बाजारों का विकास और केंद्रीय बैंक की भूमिका; भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सामने उभरते मुद्दे और चुनौतियां; और वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था। अंतिम प्रकाशित आरसीएफ वर्ष 2013 में था और इसने वित्तीय-मौद्रिक समन्वय के विषय को संबोधित किया। तब से, एक विराम चल रहा है।

8. आरसीएफ को विषय और दिशा देने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले और बाद में मेरे साथ काम करने वालों में से कइयों ने कहा कि उनके अंदर एक प्रबल इच्छा प्रसुप्त है कि इसे पुनर्जीवित करें और इस प्रकार एक ऐसी परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठित करें जो रिजर्व बैंक जितनी ही पुरानी है। वे अक्सर मुझसे कहते कि जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस नामक

पुस्तक से वे प्रेरणा लेते हैं जो उन्होंने 1908 में ब्रिटिश सिविल सेवा छोड़ने के बाद लिखी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारतीय मौद्रिक मुद्दों पर व्याख्यान देते थे। यह 1913 में उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक थी, इसके प्रकाशन में इस कारण से कुछ जल्दी की गई कि उन्हें उस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस में एक पद की पेशकश की गई थी, जो उनके लिए नीति को प्रभावित करने का एक बड़ा अवसर था। यह पुस्तक उस समय की भारतीय मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली की अपनी समीक्षा के लिए अलग पहचान रखती है। इसके कुछ अमूल्य रत्न इस प्रकार हैं: इस परिकल्पना को ध्वस्त करना कि देश के विदेशी व्यापार के लिए एक मूल्यहास वाली मुद्रा फायदेमंद है, और इसके बजाय इसके मुद्रास्फीतीय परिणामों पर ध्यान ले जाना; स्वर्ण मान (गोल्ड स्टैंडर्ड) के बजाय उस समय भारत के स्वर्ण विनिमय मान की उपयुक्तता; किसी धातु मानक की तुलना में एक कागजी मुद्रा प्रणाली में लोच का लाभ; और ब्याज दरों को उन वर्षों के प्रचलित स्तर की तुलना में और अधिक उचित स्तर तक कम करने की आवश्यकता।

9. जिस बात ने मुझे प्रभावित किया, वह थी भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक (उन्होंने इसे स्टेट बैंक कहा) के लिए उनकी वकालत: "ऐसा बैंक, जो अपने लेनदेन को बैंकिंग सिद्धांतों और व्यवसाय तक ही सीमित रखता हो, और संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हो और पर्याप्त पूंजी के साथ, विवेकपूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के तहत, भारतीय वाणिज्य के समग्र उन्नयन के लिए इस देश की अतिरिक्त पूंजी के एक हिस्से के नियोजन में सहायता देकर, भारत की मौद्रिक प्रणाली को स्थिरता देकर, और उन सामयिक उतार-चढ़ावों को रोककर, जो इसे अभी झेलने पड़ रहे हैं, यह सार्वजनिक कल्याण का एक माध्यम बने..."। पुस्तक के अंत में उन्होंने अपने अनुभवों से भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का स्पष्ट विश्लेषण किया जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है: भारतीय प्रणाली अत्यधिक सुसंगत है। प्रणाली (सिस्टम) का हर हिस्सा किसी न किसी हिस्से में फिट बैठता है ... लेकिन प्रणाली की जटिलता और सुसंगतता को ऐसे किसी के लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है जो उसके अंगों के गुण-दोषों को बताता रहे। यह भारतीय वित्त का अनूठापन नहीं है। यह सभी मौद्रिक समस्याओं की विशेषता है ... मैं यह जोर देकर कहना चाहूँगा कि, अपने स्वर्ण-विनिमय मान में, और जिस तंत्र का इसे सहयोग प्राप्त है, भारत, असंगति से बहुत दूर, मौद्रिक प्रगति में अग्रणी है। लेकिन अपनी बैंकिंग व्यवस्थाओं में, अपने नोट निर्गम के प्रबंधन में, और अपनी सरकार के मुद्रा बाजार के संबंधों में, उसकी स्थिति असंगत है; और अन्यत्र जो कुछ किया जाता है, उससे उसे बहुत कुछ सीखना है।" रिजर्व बैंक में पेशेवर अनुसंधान पर कीन्स की पहली पुस्तक का प्रभाव वाकई इतना गहरा था कि स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक दशक में, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट (रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस) के एक खंड को भारतीय मुद्रा और वित्त (इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस) कहा जाता था।

10. मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट को फिर से शुरू करने की प्रेरणा अंदर से आई। हमारी अनुसंधान टीम उत्साहपूर्ण युक्तियों के साथ मेरे पास आती और इतिहास व परंपरा दोनों का समान रूप से आवाहन करते हुए आंतरिक अनुसंधान और विचारों के विकास को अभिव्यक्ति देने की बात कही जाती जिसे कई बार मैंने अपने आस-पास के परिवेश के समकालीन घटनाक्रम को पूर्वसूचित करता हुआ पाया। और जब रिजर्व बैंक को लंबे समय से देख रहे एक प्रमुख विचारक का एक मृदु प्रोत्साहन मिला, तो मैं सहमत हो गया³। हमने एक विषय की खोज की और भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन के क्रम में मौद्रिक नीति संरचना की व्यापक समीक्षा से बेहतर और क्या हो सकता था! यह एक उपयुक्त विषय है। इस प्रमुख संरचनात्मक सुधार के

3 बिजनेस स्टैंडर्ड में 3 टी सी ए श्रीनिवास राघवन, 18 जनवरी, 2020

लगभग पाँच वर्षों के अनुभव के साथ, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अब रिज़र्व बैंक की एक उपलब्धि है, बावजूद इसके कि इसको लेकर प्रारंभ में काफ़ी संशय और हिचकिचाहट थी, जो कि मुझे लगता है, अभी भी है। हालाँकि, कोविड-19 के आने तक, घरेलू और बाहरी दोनों पक्षों से इसे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, विश्लेषकों और बहुपक्षीय संस्थानों की अच्छी स्वीकार्यता और यहाँ तक कि सराहना भी मिली थी। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संप्रेषण की स्पष्टता के पक्ष में एक औपचारिक संरचना होने के नाते, व्यावहारिक दैनिक केंद्रीय बैंकिंग के कार्य में हम इसकी बारीकियों और उनके परस्पर आदान-प्रदान के साथ जुड़ते आ रहे हैं। कुछ जोरदार बहस इस बात पर भी हुई है कि इस संरचना द्वारा मूल्य स्थिरता को दी गई प्रधानता तथा मजबूत व निरंतर विकास, जो कि किसी उदीयमान अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है, की साथ चलने वाली और प्रायः हावी हो जाने वाली चिंताओं के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा। लगभग इसी समय कई प्रमुख केंद्रीय बैंक भी संरचनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

11. कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने जीवन और आजीविका को अस्त-व्यस्त कर दुनिया के लोगों को भीषण तनाव में ला दिया, जिससे बाध्य होकर राजकोषीय, मौद्रिक और वित्तीय नीतियों को अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं से बाहर जाकर अभूतपूर्व कार्रवाईयां करनी पड़ीं। हम में से कुछ संक्रमित थे, कुछ अस्पताल में भर्ती थे और हम सभी खतरे में जी रहे थे। फिर भी, हम बच गए और इसकी कहानी सुना रहे हैं।

12. देश के अनुभव पर आधारित, 1998-99 में शुरू हुई थीम-आधारित संस्करणों में इस 12वीं रिपोर्ट के विचार का विषय है 2016 में भारत के लिए मौद्रिक नीति संरचना के रूप में अधिनियमित लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) संरचना, भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता और आगे का रास्ता। रिपोर्ट निम्नलिखित का मूल्यांकन कर रही है : मुद्रास्फीति लक्ष्य का स्तर और उभरती समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थितियों में इसकी उपयुक्तता की दृष्टि से इसके आस-पास का सह्य दायरा, वृद्धि का उद्देश्य और एफआईटी के साथ दोहरे अनिवार्यताओं की परंपरा में इसकी संगति, परिचालन प्रक्रिया और संचरण के मुद्दे, प्रक्रियात्मक और संस्थागत प्रक्रियाओं से जुड़े विषय और वैश्वीकृत वातावरण में मौद्रिक नीति के संचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दे। यह सब एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखा गया है जो उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिनके तहत मौद्रिक नीति संरचना एक अनिवार्यता बन गई, कुछ पूर्व-शर्तों और विधायी प्रक्रियाओं की क्रमिक और नपी-तुली स्थापना जो इसके परिचालन और उत्तरदायित्व के लिए कानूनी संस्थागत व्यवस्थाओं को लागू करती है, और नई संरचना के अनुभव का आकलन। आख्यान में उन कठिन चुनौतियों का स्पष्ट चित्रण है, जो इन प्रारंभिक वर्षों में, विशेष रूप से वैश्विक वातावरण में हमें पेश आई, साथ ही साथ इसे अपनाने से हुए अप्रत्याशित लाभों का भी। पर एक महत्वपूर्ण सतर्कता जो ध्यान में यहाँ रखनी है, वह यह है कि डेटा संग्रह, सुसंगति, कवरेज और गुणवत्ता में समस्याओं के कारण इन विश्लेषणों और आख्यानो में कोविड-19 महामारी वाली अवधि शामिल नहीं है।

13. अंत में, पेशेवर अनुसंधान कर्मियों की टीम पर कुछ शब्द कहना उचित होगा जिन्होंने महामारी के समय में अथक प्रयास से विचारों के विकास को एक साकार रिपोर्ट में बदला। विषय (थीम)-आधारित रिपोर्टों का उद्देश्य विश्लेषणात्मक जाँच और आँकड़ा-आधारित प्रमाणीकरण वाली नीति-उन्मुख अनुसंधान ऊर्जा को राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने वाले सामयिक मुद्दों के रूप में लाना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परीक्षण योग्य परिकल्पना का सत्यापन तथ्यों से करना और निष्कर्षों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना है ताकि सार्वजनिक पाठकों को समसामयिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में विषय का अपनी संपूर्णता में एक व्यापक, संतुलित और गहन मूल्यांकन प्रदान किया जा सके। दैनिक आधार पर जनता का ध्यान खींचने वाले मौद्रिक नीति के मुद्दे और एक नई मौद्रिक नीति संरचना के अंतर्गत पहले के कुछ वर्ष अनुसंधान ऊर्जाओं को एक उपयोगी सार्वजनिक जुड़ाव की ओर मोड़ने का एक समृद्ध अवसर इस आरसीएफ को प्रदान करते हैं।

14. आरबीआई की टीम ने लगातार मेहनत की, महामारी के चलते आई हर बाधा व हर कठिनाई को चुनौती दी, और साथ ही बड़ी कर्मठता से अन्य प्रमुख रिपोर्टों, सांख्यिकी व सर्वेक्षणों, और मौद्रिक नीति समिति को दी जाने वाली प्रस्तुतियों सहित दूसरे सभी कार्यों की समबद्धता का ध्यान रखा। थीम के लिए प्रासंगिक विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोणों की विविधता और मतभेदों के साथ टीम के सदस्यों ने एक-दूसरे को भी चुनौती दी। वरिष्ठों ने अपने युवा सहकर्मियों का मार्गदर्शन किया और इससे न केवल विविधता बल्कि निरंतरता और अतिरिक्त लोगों को तैयार करने में भी मदद मिली। उधर से हमारे युवा पेशेवर अनुसंधानकर्ता नए विचार लेकर आए और पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। विचारों के इस प्रतिस्पर्धी विकास ने मुझे मुग्ध किया और मेरी सराहना भी अर्जित की।

15. हर संकट उपयोगी सीख देता है। कोविड-19 महामारी ने पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों नीतियों की हदें परख ली हैं। खास तौर पर, मौद्रिक नीति प्राधिकारी, दुनिया भर में निर्णायक मोड़ पर हैं। ऋणात्मक ब्याज दरें, मात्रात्मक और ऋण सुलभता जैसी घटनाएं, और दीर्घावधि भावी मार्गदर्शन मानक मॉडलों की परीक्षा ले रही हैं। इसके अलावा, उनके कंधों पर अभूतपूर्व प्रतिसादों का भारी बोझ तथा कुआं और खाई वाली कठिन दुविधा है, अवलंबों को क्रमशः समेटें या नहीं और अगर उन्हें अधिक समय तक नीतिगत अवलंब को जारी रखना पड़े तो आदत-ग्रस्तता के प्रभावों (रैंप इफेक्ट्स) का नैतिक खतरा। इस बीच, एक ही साथ मांग और उत्पादन में कमी, लोगों की जीवन शैली और प्राथमिकताओं में मूलभूत परिवर्तन और उनके आस-पास के परिवेश में विशाल परिवर्तन उनके नीतिगत संरचनाओं को चुनौती दे रहे हैं। इस परिवेश में, मौद्रिक नीति प्राधिकारियों के लिए प्रभावी और प्रासंगिक बने रहने का प्रयास आवश्यक है। यह रिपोर्ट इस अस्तित्ववादी विमर्श में शामिल हो गई है और आशा है कि यह प्रकाश डालेगी न कि उलझाएगी। मैं रिजर्व बैंक की इस टीम के प्रयासों की सराहना करता हूँ और यह रिपोर्ट पाठकों को प्रस्तुत करता हूँ।

शक्तिकांत दास

गवर्नर

26 फरवरी 2021